

बजट 2025: जम्मू-कश्मीर को केंद्रीय बजट में मिली 50 हजार करोड़ की ऐतिहासिक सहायता; परियोजनाओं में आएगी तेजी

जम्मू

केंद्रीय बजट में इस बार जम्मू-कश्मीर के हिस्से 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आए हैं। इसमें केंद्रीय सहायता, जम्मू-कश्मीर पुलिस के वेतन आदि के लिए प्रावधान हैं। बर्फबारी, भूखलन की समस्याओं से जूझने वाले जम्मू-कश्मीर का बजट में खास ख्याल रखा गया है।

प्रदेश को आवंटित बजट में इस बार भी ज्यादातर हिस्सा केंद्रीय सहायता का है। केंद्रीय योजनाओं, आपदा राहत निधि, पुलिस के खर्चों और निवेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का बजट में बढ़ोबस्त किया गया है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में चल रही मौजूदा केंद्रीय परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी।

बजट प्रावधानों के अनुसार इस बार भी प्रदेश की पुलिस के लिए 9,325 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुदान और ऋण सहित अन्य मदों में 41,000.07 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें केंद्रीय सहायता के रूप में 40,619.30 करोड़ रुपये मिले हैं।



आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 297 करोड़ रुपये का प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और राहत कार्य में बड़ी मदद मिलेगी। विकास से जुड़ी परियोजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 101.77 करोड़ रुपये मिले हैं। पिछले बजट में अनुदान, ऋण व अन्य मदों में प्रदेश को 42,277.74 करोड़ रुपये मिले थे। इस बार राज्य को इससे ज्यादा की उम्मीद थी।

पर्यटन को बढ़ावा देनी रियायती हेलिकॉप्टर सेवा, प्रदेश में छात्राओं के लिए बनेंगे हॉस्टलरियायती हेलिकॉप्टर सेवा के लिए 5 करोड़ रुपये पृष्ठ 15 पर

उपराज्यपाल ने संसद में माननीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री द्वारा प्रस्तुत 2025-26 के केंद्रीय बजट की सराहना की। उपराज्यपाल ने एकस पर पोस्ट किया है, विकसित भारत के लिए व्यावहारिक बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को मेरा हार्दिक धन्यवाद। अर्थव्यवस्था को तेजी से पटारी पर लाने और गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए साहसिक विकास पहल के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ। मध्यम वर्ग को बड़ा प्रोत्साहन संशोधित कर दर संरचना मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय प्रधान मंत्री ने किराए पर टीडीएस सीमा बढ़ावा, सामाजिक सुरक्षा बढ़ावा और गिरा अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाकर करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। बजट 2025-26 त्वरित विकास और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने की

जम्मू



शेष पृष्ठ 15 पर

जम्मू के अखनूर में चिकित्सा स्थितियों के कारण सेना के कैप्टन की मृत्यु



जम्मू

रविवार को जम्मू के अखनूर इलाके में चिकित्सा स्थितियों के कारण सेना के एक युवा कैप्टन की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह अचानक गिर गए और उन्हें कल देर शाम सैन्य अस्पताल अखनूर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि वाराणसी के रहने वाले अधिकारी की हालांकि चिकित्सा स्थितियों के कारण मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ गृह नगर में किया जाएगा।

ओटीएम मुंबई पर पर्यटन हितधारकों ने मुख्यमंत्री, पर्यटन विभाग के प्रति संतुष्टि घोषित की

आशा है कि आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम में और अधिक लोग आएंगे

मुंबई

जम्मू-कश्मीर के यात्रा और पर्यटन उद्योग ने उम्मीद जताई है कि ओटीएम में जम्मू-कश्मीर सरकार की सफल भागीदारी से यूटी में अधिक पर्यटक आएंगे, हालांकि उन्होंने आयोजन में यूटी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पर्यटन विभाग को भी धन्यवाद दिया है।

जम्मू-कश्मीर में पर्यटन उद्योग पर चल रहे ओटीएम के नीतीजे पर आशावाद व्यक्त करते हुए, व्यापार नेताओं ने उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।



और समन्वय सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता का भी स्वागत किया।

पर्यटन उद्योग के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए उनकी और पर्यटन विभाग की सराहना की, उनका नेतृत्व आईएटीओ के अध्यक्ष नासिर शाह ने किया और इसमें ट्रैवल एजेंट्स सोसाइटी ऑफ कश्मीर, जम्मू और कश्मीर

शेष पृष्ठ 15 पर

हथियार दिखाकर ग्रेटर कैलाश में दिनदहाड़े डैकेती; 1.5 किलोग्राम लूटा सोना, जांच में जुटी पुलिस



जम्मू

ग्रेटर कैलाश में आभूषणों की दुकान में वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश एक बिना नंबर की स्प्लैन्डर बाइक से पहुंचे थे। वहीं, बाद में इसी से फरार हुए हैं। इनके भागने के बाद पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली। फल्गुरा चौक से जैसे-जैसे पुलिस सीसीटीवी खंगालती गई वैसे ही उनका रुट पता चलता गया।

अंतिम लोकेशन मुरारी चक गांव की थी। इसी गांव से ये रिंग रोड पर चढ़े और फिर वहां से गायब हो गए। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद बदमाशों ने अपना हुलिया नहीं बदला। शेष पृष्ठ 15 पर

उमर अब्दुल्ला की कद्दूरता बर्दशत नहीं की जाएगी-डॉ अभिजीत जसरोटिया

कठुआ

डॉ. अभिजीत सिंह जसरोटिया ने कहा कि बीटिंग द रिट्रीट समरोह में शामिल न होकर, एक मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने लोकतंत्र, भारत के संविधान और भारत के 148 करोड़ लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है।

डॉ. अभिजीत सिंह जसरोटिया, डॉ. प्रदीप महोत्रा राज्य मीडिया सचिव भाजपा और डॉ. परनीष महाजन प्रभारी प्रशिक्षण विभाग के साथ, पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह इतिहास में पहली बार है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के मंत्री उस समारोह में शामिल नहीं हुए हैं जो हमारे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के उत्सव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि वह भारत के संविधान के कारण मुख्यमंत्री हैं और भारत गणराज्य द्वारा संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले दिन को चूकने की गलती नहीं करनी चाहिए।



मन में वास्तव में इसके लिए कोई सम्मान नहीं है।

डॉ. अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने संवाद किया कि क्या वह अकबर लोन के झूँका सहारा ले रहे हैं और पाक जिंदाबाद के नारे लगान की तैयारी कर रहे हैं। जसरोटिया ने कहा कि सीएम उमर अभी भी गण-तंत्र के बजाय परिवार-तंत्र में रह रहे हैं, ज्योतिक वह गण-तंत्र के उत्सव को चिह्नित करने के लिए समारोह में भाग लेने के लिए सरकारी अधिकारियों के सभी नियंत्रणों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करते हैं। जसरोटिया ने कहा

कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारत के 148 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खेला है और सीएम उमर से जवाब देने को कहा कि क्या उहोंने और उनके मंत्रिपरिषद ने जानबूझकर लोकतंत्र के उत्सव को छोड़ दिया है। जसरोटिया ने राजनीतिक व्यक्तियों के उस वर्ग की आलोचना की जो अभी भी भारत के संविधान के समानांतर एक और संविधान लाने के बारे में सोचते हैं और भारतीय गणराज्य के तिरंगे के सामने एक और झंडा फहराना चाहते हैं।

उपराज्यपाल ने हैदराबाद में दक्षिण भारत बीएचयू पूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित किया 1916 में अपनी स्थापना के बाद बीएचयू ने स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को पोषित किया और लोगों में चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई-एलजी सिन्हा

हैदराबाद

उपराज्यपाल मोज निभाई ने हैदराबाद के आईआईसीटी ऑफिटिनिंग में दक्षिण भारत बीएचयू पूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित किया।

अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने बनारस हिंदू विष्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी।

उपराज्यपाल ने कहा कि बीएचयू के पूर्व छात्रों का सम्मेलन महामना पड़ित मदन मोहन मालवीय के दृष्टिकोण और प्रभावशाली सामुदायिक निर्माण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। महामना का दृष्टिकोण एक ऐसा विष्वविद्यालय बनाना था जो एक नए भारत का निर्माण करेगा। बीएचयू ने उनका सपना सफलतापूर्वक पूरा किया। इसने न केवल हमारे मूल आदर्शों, परंपरा और मूल्यों को संरक्षित किया है, बल्कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को बदलकर देश की नियति को भी आकार दिया है।

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में ताजा बर्फबारी से प्रशासन हाई अलर्ट पर

जम्मू

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बर्फबारी का ताजा दौर शुरू हो गया है, जहां ऊर्चाई वाले कई इलाकों में एक फुट से ज्यादा बर्फ जम गई है। बर्फबारी ने जिले के ऊपरी इलाकों में कई इलाकों को प्रभावित किया है और प्रशासन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पहुंच मार्गों को साफ करने के लिए हाई अलर्ट पर है। सब-डिविजनल मार्जिस्ट्रेट (एसडीएम) नूराबाद, बरीर उल हसन ने कहा कि सुबह-सुबह सभी प्रमुख सड़कों को साफ कर दिया गया और संबोधित विभाग सुचारू संपर्क बनाए रखने के लिए मर्शीनरी के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों के लिए सलाह जारी की है जिसमें उन्हें यात्रा करते समय सावधानी बरतने और मौसम की स्थिति के बारे में अपडेट रखने का आग्रह किया गया है। स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए जिला अधिकारी आवश्यक संसाधनों और कर्मियों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें, खासकर ऊर्चाई वाले इलाकों में और प्रशासन द्वारा जारी सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें।

केंद्रीय मंत्रियों को उपहार में दिए गए शॉल वापस मांगे मुख्यमंत्री : लोन

श्रीनगर

केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर को उम्मीद से कम धन मिलने का आरोप लगाते हुए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को उपहार मंडे दिए गए शॉल वापस मांगें। साथ ही गांदरबल जिले के सोनमर्ग में बादल रहित मौसम पर की गई अपनी टिप्पणी को संशोधित करें।

एक्स पर लोन ने लिखा है कि केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर के आवंटन में इस बार कमी की गई है। केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर को प्रस्तावित आवंटन लगभग 41,000 करोड़ रुपये है। यह पिछले आवंटन से लगभग 1,000 करोड़ कम है। मुद्रासंपत्ति के लिए समायोजित करने पर इसमें 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये की ओर कमी की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य स्कीडिंग और सेल्फी से कहीं आगे तक जाता है। यह एक गंभीर और पवित्र व्यवसाय है। जो करना है, करो।

एसडब्ल्यूडी ने रीचा फाउंडेशन के सहयोग से कटिंग और टेलरिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया



सांचा

मैं मौजूद, आजीविका प्रशिक्षण के लिए 40 से अधिक स्थानीय महिलाओं को नामांकित किया गया था।

इस अवसर पर बोलते हुए, संकल्प: एसडब्ल्यूडी टीम ने सभी लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपना स्वयं का सेटअप खोलने के लिए प्रेरित किया जिसके माध्यम से वे अपनी आजीविका उत्पन्न कर सकें। संकल्प टीम ने विभिन्न महिला केंद्रों के बारे में बताते हुए महिलाओं और लड़कियों के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर जागरूकता बढ़ाई। अंत में सभी लाभुकों के बीच जलपान का भी वितरण किया गया।

टीम ने उम्मीदवारों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जो उनके स्व-रोजगार उद्यम खोलने के लिए फायदेमंद हैं और प्रतिभागियों को आशासन दिया कि विभाग उन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ बैंकर्ड-फॉर्मर्ड लिंकेज प्रदान करके अपने स्टार्ट-अप खोलने के लिए मार्गदर्शन करेगा।

डीआईपीआर ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे संस्करण की मेजबानी की



जम्मू

सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू और कश्मीर ने कन्वेशन सेंटर में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे संस्करण का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में प्रथमता वैज्ञानिक एक साथ आए, जिन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी में अग्रणी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की दूरदर्शी विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक व्याख्यान दिए। दूसरे संस्करण के लिए व्याख्यान श्रृंखला का विषय था, 'सपनों की शक्ति: कैसे बढ़े विचार दुनिया को बदल सकते हैं'।

व्याख्यान श्रृंखला में दो प्रतिष्ठित वक्ता शामिल थे जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता साझा की और अपनी विचारोत्तेजक प्रस्तुतियों से दर्शकों को प्रेरित किया।

पूर्व प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, इसरो के एसोसिएट निदेशक और इसरो के पूर्व सीरीज ध्वनि प्रोफेसर डॉ. वेलंकी शेषगिरी राव ने इस विषय

कक्षा से ब्रह्मांड तक, अंतरिक्ष अन्वेषण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रेरणादायक यात्रा पर व्याख्यान दिया।

डॉ. राव के व्याख्यान में डॉ. कलाम के इस विश्वास पर प्रकाश डाला गया कि ज्ञान और नवाचार, जब कक्षाओं में पोषित होते हैं, तो मानवता को अकल्पनीय ऊँचाइयों, यहां तक कि ब्रह्मांड तक भी ले जा सकते हैं।

उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भविष्य की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

एनआईएस, आईआईएससी में सहायक प्रोफेसर और सीएसआईआर के पूर्व निदेशक और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डीएसटी सलाहकार डॉ. मनोज कुमार पटेरिया ने दूरदर्शी नेतृत्व, सपनों को वास्तविकता में बदलना विषय पर बात की। डॉ. पटेरिया का व्याख्यान डॉ. कलाम के जीवन और कार्य से प्रेरणा लेते हुए महत्वाकांक्षी सपनों को मूर्त उपलब्धियों में बदलने में दूरदर्शी

नेतृत्व की भूमिका पर केंद्रित था। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सफलता हासिल करने में दृढ़ता, नवाचार और नेतृत्व के महत्व को रेखांकित किया।

अपने स्वागत भाषण में सूचना निदेशक जितन किशोर ने मिसाइल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष संगठनों में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के उल्लेखनीय योगदान के बारे में बात की। उन्होंने अनगिनत वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए एक गुरु और प्रेरणा के रूप में डॉ. कलाम की भूमिका पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि कैसे उनकी विरासत भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का मार्गदर्शन करती रहती है।

इस कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक सूचना (मुख्यालय) विवेक पुरी, संयुक्त निदेशक सूचना जम्मू अतुल गुप्ता, उप निदेशक सूचना (पीआर एंड एवी) दीपक दुबे, उप निदेशक सूचना (केंद्रीय) सुरील कुमार, उप निदेशक (पीआर) जम्मू, उप निदेशक (मुख्यालय) जम्मू, सूचना अधिकारी, लेखा अधिकारी और अन्य स्टाफ सदस्य शामिल हुए।

उपायुक्त किश्तवाड़ ने आईवाईसी-2025 के लिए गतिविधियों के कैलेंडर को मंजूरी दी, एम-पैक्स के कामकाज की समीक्षा की।



किश्तवाड़

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के लिए गतिविधियों के कैलेंडर को मंजूरी देने के लिए तीसरी जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति की बैठक उपायुक्त राजेश कुमार शबन की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

गहन चर्चा के बाद, उपायुक्त द्वारा गतिविधियों के एक व्यापक कैलेंडर को मंजूरी दी गई, जिसमें कृषि और संबद्ध विभागों के सहयोग से सहकार मेला, स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शामिल था।

समिति ने कालाजीरा, अखरोट और राजमाश में नई सहकारी समितियों/एफपीओ के गठन की योजना को भी मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, समिति ने पिछली दो संयुक्त कार्य समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

इसके अलावा, उपायुक्त ने डिटी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों और अन्य समिति सदस्यों को नई एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों के गठन में तेजी लाने की निर्देश दिया।

उन्होंने संबद्ध विभागों के सहयोग से जागरूकता शिविरों के माध्यम से सहकारी सदस्यता जुटाने के लिए संभावित पंचायतों की पहचान करने का भी निर्देश दिया।

इससे पहले, डिटी रजिस्ट्रार, सहकारिता, मिर्जा मुमताज इकबाल ने जिले में सहकारी क्षेत्र के समग्र परिवृत्ति का अवलोकन प्रदान किया।

बैठक में डिटी रजिस्ट्रार सहकारी/ईओ नगर पालिका किश्तवाड़ मिर्जा मुमताज इकबाल, एडी हस्तशिल्प प्रदीप शान, सीएचओ किश्तवाड़, साजिद मुस्तफा, डीएसएचओ किश्तवाड़, एलडीएम किश्तवाड़, डीडीएम नावार्ड, एआर सहकारी, सहकारी विभाग के कर्मचारी और अन्य उपस्थित थे।

उपायुक्त ने कटरा में एनएच-1सी भूमि अधिग्रहण स्थल और सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया



रियासी

उपायुक्त निधि मलिक ने 20 मीटर स्पान पुल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का आकलन करने के लिए कोटली मनोरोत्तेजन गांव में एनएच-1सी का स्थलीय निरीक्षण किया।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भूमि मालिकों

को मुआवजे का समय पर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पुल निर्माण तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया।

दौरे के दौरान, उपायुक्त ने सरकारी हाई स्कूल भूगो का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कक्षा की स्थिति की समीक्षा की और शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। उन्होंने साफ-सफाई और रख-

रखाव के लिए स्कूल अनुदान के उचित उपयोग पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आदेश दिया कि स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए स्कूल के सफाई कर्मचारी प्रतिदिन उपस्थित रहें।

जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निधि मलिक ने तहसीलदार को नियमित स्कूल निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने शैक्षिक बुनियादी ढांचे और छात्र

कल्याण में सुधार के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, स्वच्छता मानकों को पूरा नहीं करने पर प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया।

इस अवसर पर एसीआर अंशुमालि शर्मा, एसडीएम कटड़ा पीयूष धोत्रा, तहसीलदार कटड़ा, एक्सडीएम भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने भूमि रिकॉर्ड के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की

जम्मू

मुख्य सचिव अटल डुल्हा ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत जम्मू-कश्मीर के राजस्व गांवों के भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में वित्तीय आयुक्त राजस्व के अलावा आयुक्त सचिव एच एंड यूडीडी, सचिव राजस्व, निदेशक भूमि अभिलेख, एसआईओ एनआईसी के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, अटल डुल्हा ने डीआईएलआरएमपी के तहत भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और रखरखाव को बढ़ावा देने में यूटी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और इसे पूरा करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला।

गुणवत्तापूर्ण भूमि रिकॉर्ड के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि डिजिटल रूप से अद्यतन और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड भूमि संसाधनों के अनुकूलन और नीति और योजना में सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा वितरण की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए भूमि रिकॉर्ड तक निर्वाचन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भू-संदर्भित कैडस्टल मानचित्रों के साथ डिजिटलीकृत रिकॉर्ड का एकीकरण



आवश्यक है।

मुख्य सचिव ने विभाग पर राजस्व विशेषज्ञों की टीमों का गठन करने के लिए दबाव डाला, जो इस डिजिटल रिकॉर्ड की स्टीकता का आकलन करने के लिए जिलों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इन रिकॉर्डों की गुणवत्ता और स्टीकता की जांच करना महत्वपूर्ण है और लोगों को किसी भी विरंगनि के लिए अपने संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने में स्वयं अगे आना चाहिए ताकि इन्हें समय पर ठीक किया जा सके।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण के संबंध में, मुख्य सचिव ने इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण महत्व

देने पर जोर दिया क्योंकि यह भूमि के स्वामित्व पर स्पष्टता प्रदान करेगा और शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों को हल करेगा। अटल डुल्हा ने कहा कि कार्यक्रम के पूरा होने से यह सुनिश्चित होगा कि शहरी भूमि रिकॉर्ड स्टीक और अद्यतन होगा, जिससे शहरी नागरिक सशक्त होंगे, जीवन में आसानी होंगी और दूरी शहरी नियोजन सक्षम होंगा।

बैठक के दौरान डीआईएलआरएमपी में अब तक हुई प्राप्ति और यहां से उत्तर जाने वाले भविष्य के कदमों पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। बताया गया कि डीआईएलआरएमपी के संबंध में पर्याप्त प्राप्ति हासिल की गई है और 6850 गांवों में से 6839 में जमाबदियों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है।

बैठक के दौरान डीआईएलआरएमपी में अब तक हुई प्राप्ति और यहां से उत्तर जाने वाले भविष्य

मुख्य सचिव ने नशीली दवाओं के खतरे के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए परिणाम-उन्मुख कार्य योजना पर जोर दिया

जम्मू

शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने सूचना विभाग को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अन्य विभागों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने पोस्टर, नारे, सोशल मीडिया, सार्वजनिक परिवहन और बाहरी स्थानों पर विज्ञापनों सहित जन जागरूकता अभियानों के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने विभाग को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों और इस बढ़ते खतरे से व्यक्तियों और समाज को बचाने के तरीकों पर प्रकाश डालने वाली एक लघु फिल्म बनाने का भी निर्देश दिया।

बहु-आयामी रणनीति पर जोर देते हुए, अटल डुल्हा ने कहा कि कड़े उपायों को लागू करके, हमारा लक्ष्य नशीली दवाओं के नेटवर्क

को खत्म करना, इसकी मांग को कम करना और एक स्वस्थ, सुरक्षित समाज बनाना है।

जागरूकता कार्यक्रम छात्रों को रोकथाम रणनीतियों पर शिक्षित करने, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की भूमिका पर जोर देने, नशीली दवाओं के विरोधी अभियानों में युवाओं को शामिल करने पर केंद्रित होगा।

व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य सचिव ने पुलिस, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण और ग्रामीण विकास विभागों को प्रत्येक पंचायत को कवर करने वाली गतिविधियों का एक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया। इससे विशेषकर छात्रों और युवाओं के बीच नशामुक्त अभियान की गति तेज होगी।

उपायुक्त ने किश्तवाड़ में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की

किश्तवाड़

किश्तवाड़ के उपायुक्त राजेश कुमार शवन ने जिले में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की प्राप्ति की समीक्षा की।

बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत हुई प्राप्ति का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नोडल अधिकारी एचएडीपी/मुख्य कृषि अधिकारी, किश्तवाड़ अमजद हुसैन मलिक ने कार्यक्रम की प्रगति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल 14,314 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 10,532 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें कृषि क्षेत्र में 7,996, बागवानी में 331, पशुपालन में 1,425, भेड़ पालन में 589, रेशम उत्पादन में 167, मत्स्य पालन में 18 और विपणन क्षेत्र में 6 आवेदन शामिल हैं, जैसा कि जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

समीक्षा के दौरान, उपायुक्त ने जिले भर में पात्र उम्मीदवारों के पंजीकरण को अधिकतम करने के महत्व पर जोर दिया और कार्यक्रम में अधिक से अधिक पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की व्यापक समीक्षा भी शामिल थी।

उपायुक्त ने एचएडीपी में प्रगति सुनिश्चित करने और यूटी में शीर्ष रैंक हासिल करने के लिए नए लक्ष्य भी निर्धारित किए। इनमें कुल लक्ष्यों की संख्या किसान साथी पोर्टल के लिए 7,350, दक्ष किसान के लिए 1,600, और केकेजी एप में खेतों को जोड़ने के लिए 750 शामिल हैं।

समीक्षा बैठक में सीपीओ किश्तवाड़ शाहनवाज बाली, सीएचओ किश्तवाड़ साजिद मुस्तफा, डीएसएचओ किश्तवाड़, डीएओ किश्तवाड़, एसडीओ, एसडीएओ, एसएमएस और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों के साथ बातचीत की

कर्तव्य पथ और विभिन्न अव्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कैडेटों और एनसीसी अधिकारियों की सारहना की, अखिल भारतीय एनसीसी लड़कियों की टुकड़ी का नेतृत्व करके जम्मू-कश्मीर को गौरवान्वित करने के लिए एसयूओ एकता कुमारी को बधाई दी।

मैं चाहता हूं कि युवा जम्मू-कश्मीर की परिवर्तनकारी यात्रा का नेतृत्व करें-एलजी सिन्हा

एनसीसी की भावना उन्हें शांति और प्रगति के मिशन को शक्ति देने और रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी-एलजी सिन्हा

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख एनसीसी निदेशालय के कैडेटों ने गणतंत्र दिवस शिविर में अपने अनुभव साझा किए

जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने के बाद लौटे एनसीसी कैडेटों के साथ बातचीत की।

गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेटों ने अपने अनुभव साझा किये। उपराज्यपाल ने एकत्व पथ और विभिन्न अन्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन



के लिए कैडेटों और एनसीसी अधिकारियों की सारहना की। उन्होंने अखिल भारतीय एनसीसी लड़कियों की टुकड़ी का नेतृत्व करके जम्मू-कश्मीर को गौरवान्वित करने के लिए एसयूओ एकता कुमारी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में ऐतिहासिक भागीदारी, कई प्रतिष्ठित पुस्कार और प्रशंसा हासिल करने से देश के भावी नेताओं को तैयार करने में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका मजबूत ढूँढ़ है।

उपराज्यपाल ने कहा एनसीसी कैडेटों ने हमेशा असाधारण कौशल, अनुशासन दिखाया है और समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। मुझे समाज के विकास और सुधार तथा नवीन समाधानों और निःस्वार्थ सेवा के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारे युवा कैडेटों के विचार और ऊर्जा की

सारहना करनी चाहिए।“

उपराज्यपाल ने कहा, “युवा भविष्य हैं, वे एक बेहतर दुनिया और जम्मू-कश्मीर के उत्तर कल के लिए हमारी आशा हैं। हमारी प्राचीन सभ्यता के आदर्शों और मूल्यों को आगे बढ़ाने और एक मजबूत जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करने की युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। एनसीसी की भावना उन्हें शांति और प्रगति के मिशन को शक्ति देने और रचनात्मक सामाजिक परिवर्तनों के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। एनसीसी कैडेटों को युवाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में योगदान देने के लिए प्रेरित और प्रोत्ताहित करना चाहिए।

उपराज्यपाल ने एनसीसी कैडेटों से पांच संकल्पों यानी जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास, नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता, राष्ट्र निर्माण

के लिए समर्पित सामाजिक इकाइयों का निर्माण, एनसीसी के आदर्शों और मूल्यों के माध्यम से रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने और देश की विकास यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने पर काम करने को कहा।

उपराज्यपाल ने दल की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कैडेटों को उत्कृष्टा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।

इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक, वीएसएम, मेजर जनरल ए. बेवली ने उन्हें एक स्मृति चिह्न भेंट किया। उपराज्यपाल ने एनसीसी की पहल को उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

भारत की विविधता में एकता के प्रतीक

एनसीसी कैडेटों के जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन को उपराज्यपाल से विशेष सराहना मिली।

इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में जम्मू कश्मीर और लद्दाख एनसीसी निदेशालय के कुल 127 कैडेटों ने भाग लिया था। 17 एनसीसी कैडेटों को कर्तव्य पथ पर मार्च करने के लिए और 05 कैडेटों को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चुना गया।

एसयूओ एकता कुमारी ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2025 के दौरान अखिल भारतीय एनसीसी लड़कियों की टुकड़ी का नेतृत्व किया, भारत के गण्डपति और डीजी एनसीसी प्रशस्ति कार्ड से सराहना अर्जित की।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पहचानी जाने वाली जेयुओ अबिदा अफरीन को रक्षा मंत्री प्रशस्ति कार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें इस साल के अंत में मार्ट एक्सेस पर चढ़ने के लिए भी चुना गया है, जो महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए एक रोल मॉडल और प्रेरणा के रूप में काम करेगी। शिविर के दौरान उनके असाधारण योगदान के लिए एसयूओ एकता, कैडेट अलंकृता शर्मा, एनओ डॉ. डॉ. लेफिटेनेंट नितिका कुंदन और सेकेंड ऑफिसर अशाक हुसैन को डीजी एनसीसी कमेंटेशन कार्ड से सम्मानित किया गया।

आकस्मिक कमांडर कर्नल अमित भारद्वाज और नायब सूबेदार यशवीर सिंह को भी डीजी एनसीसी मेडलिंग से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, दल के 8 कैडेटों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित डीजी एनसीसी पदक से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख एनसीसी निदेशालय के विष्णु अधिकारी और प्रशिक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग और राजभवन के अधिकारी भी उपस्थित थे।



FIND YOUR PERFECT
WEDDING MAKEUP
LOOK

BOOK AN APPOINTMENT NOW TO AVAL AMAZING OFFERS

BOOK NOW

① 8082520701 | 9055520701 ② H.O.: BARI BHARAMNA B.O.: GANDHI NAGAR



मुख्य सचिव ने कठुआ औद्योगिक संपदा का दौरा किया, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का आश्वासन दिया

कठुआ

मुख्य सचिव अटल डुब्लू ने घट्टी और भागथली सहित औद्योगिक संपदा कठुआ का दौरा किया।

उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी थी, जिसमें आयुक्त सचिव उद्योग और वाणिज्य विकास जीत सिंह, एमडी जैफीडीसीएल मोहम्मद यासीन चैधरी, निदेशक उद्योग और वाणिज्य जम्मू अरुण मन्हास तथा प्रबंध निदेशक सिड्को/एसआईसीओपी इंद्रजीत, उपायुक्त कठुआ राकेश मन्हास, एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना, एडीसी कठुआ रणजीत सिंह, जीएम डीआईसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने देवयानी फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एक आइसक्रीम विनिर्माण संयंत्र और घट्टी में वरुण बेवरेजेज लिमिटेड समेत विभिन्न



औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्योगों के अधिकारियों से बातचीत की और उनके सामने आने वाली सुविधाओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी ली।

अटल डुब्लू ने भागथली में कंधारी ग्लोबल बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड का भी दौरा किया। जहां अधिकारियों ने उन्हें संयंत्र और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी।

मीडिया को जानकारी देते हुए, मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पॉलिसी रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा जेके

यूटी में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की ओर से 28,400 करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है।

मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे और सिंगल-विंडो मंजूरी सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्य सचिव ने औद्योगिक विकास में पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने उद्योगों को पर्यावरण कानूनों और मानदंडों का पालन करने और अपने संचालन में पर्यावरण-अनुकूल प्रशासनों को अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने आवश्यक नियमों का अनुपालन करें।

बाद में, मुख्य सचिव ने डीसी कार्यालय परिसर के सम्मलन हॉल में घटी, कठुआ और भागथली औद्योगिक संपदा के उद्योगपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में क्षेत्र में उद्योगों की सुविधा के लिए प्राथमिकता के आधार पर उत्तराएं जाने वाले मुद्दों को खेड़ाकित करने के अलावा इन संपदाओं में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चैधरी ने सेरी में जनपहुंच कार्यक्रम आयोजित किया



सार्वजनिक शिकायतों को हल किया, त्वरित निवारण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया

सेरी (राजौरी)

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चैधरी ने सेरी में एक जनपहुंच कार्यक्रम आयोजित किया, जहां स्थानीय निवासियों की एक बड़ी भीड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जनता की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्होंने विभिन्न विकासात्मक चिंताओं को उठाया और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

लोगों द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दों में सरकारी कार्यालयों के लिए बहुमंजिला इमारत का निर्माण, स्कूलों का उन्नयन, और स्कूलों और सेरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शिक्षण और चिकित्सा कर्मचारियों की

भारी कमी शामिल थी।

इसके अतिरिक्त, जनता ने तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती, एक्स-रे मशीन और प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना, डेंटल चेयर का प्रवधान और कलाल और सेल में नए पशु चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की मांग की। अन्य गंभीर चिंताओं में ग्रिड स्टेशन के लिए लंबित प्रशासनिक स्वीकृति, बिजली के खंभों और तारों की मांग, नए ट्रांसफार्मर की स्थापना और विभिन्न पंचायतों में मौजूदा ट्रांसफार्मर का उन्नयन शामिल है। लोगों ने जल जीवन मिशन कार्यों में तेजी लाने, पंचायतों के विभाजन और चेक बांधों के निर्पाण की भी मांग की।

प्राथमिकता के आधार पर आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और समाधान के लिए निर्देश जारी किए गए।

जनता की शिकायतों पर ध्यान देते हुए उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चैधरी ने प्रशासन का

प्रमुख निर्देश जारी किए।

उन्होंने कमियों को दूर करने के लिए स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों के युक्तिकरण का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर पंचायत तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार काम किया जाना चाहिए।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे केवल फील्ड स्टाफ के फीडबैक पर निर्भर न रहें, बल्कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पंचायत का दौरा करें और जमीनी स्थिति का आकलन करें।

उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि भ्रष्टाचार बदाश नहीं किया जाएगा और कमीशन संस्कृति समाप्त होनी चाहिए। आवश्यक जनसुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।

उपमुख्यमंत्री ने जम्मू पॉलिटेक्निक कॉलेज का दौरा किया, संकाय सदस्यों, छात्रों से बातचीत की



जम्मू।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चैधरी ने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू का दौरा किया और संस्थान के कामकाज की समीक्षा की।

उनके साथ कॉलेज के वरिष्ठ संकाय सदस्य भी थे।

कॉलेज परिसर के अपने व्यापक दौरे के दौरान, उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न संकायों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को प्रदान की जा रही कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया।

संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं को विभिन्न कौशल प्रदान करने और उन्हें विभिन्न औद्योगिक व्यापारों में प्रशिक्षित करने का एक

उपमुख्यमंत्री ने कटुआ का व्यापक दौरा किया

निष्पक्ष औद्योगिक विस्तार, पर्यावरण संरक्षण का आशवासन दिया

कटुआ

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चैधरी ने कटुआ का दौरा किया और बरवाल में सिडिको के तहत औद्योगिक विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित चिंताओं का आकलन करने के लिए स्थानीय निवासियों, हितधारकों और अधिकारियों के साथ बातचीत की। उपमुख्यमंत्री ने संतुलित और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता देहराई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय आबादी, पर्यावरण और औद्योगिक विकास के हितों में सामंजस्य हो। प्रभावित निवासियों और उद्योग प्रतिनिधियों से बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने आव्वासन दिया कि सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने में सतर्क और समावेशी दृष्टिकोण अपना रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी परियोजनाओं का लाभ सभी हितधारकों, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों तक पहुंचे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिकरण आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यावरणीय स्थिरता और जन कल्याण को ध्यान में खेत देहराई इसे जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा सरकार भूमि अधिग्रहण के संबंध में लोगों की चिंताओं और उनकी आजीविका पर प्रभाव से पूरी तरह अवगत है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इन विकास परियोजनाओं से कोई भी व्यक्ति अनुचित रूप से प्रभावित न हो। औद्योगिक विस्तार को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ-साथ चलना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास उपाय मिले।"

अपने दौरे के दौरान, उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में बरवाल क्षेत्र में 250 से अधिक पेड़ों



की बड़े पैमाने पर कटाई के मुददे को भी हल किया, जो सिडिको के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हुई थी।

घटना पर सार्वजनिक आक्रोश को स्वीकार करते हुए, उन्होंने आव्वासन दिया कि यह निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत जांच की जाएगी कि पेड़ काटने के लिए आवश्यक मंजूरी किसने दी और क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

उन्होंने कहा जम्मू और कश्मीर का परिस्थितिक संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम औद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण संबंधी

चिंताओं से समझौता नहीं कर सकते। मैंने अधिकारियों को बरवाल में पेड़ काटने की घटना की व्यापक जांच शुरू करने का निर्देश दिया है, और पर्यावरण मानदंडों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पर्यावरणीय क्षति को कम किया जाए, वनीकरण कार्यक्रम और हरित औद्योगिक प्रथाओं जैसे वैकल्पिक उपायों की खोज कर रही है।

औद्योगिक विकास संबंधी चिंताओं के अलावा, उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्र में मादक पदार्थों

की तस्करी, अवैध खनन और औद्योगिक माफियाओं द्वारा उत्पन्न बदली चुनौतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को कमज़ोर कर रहे हैं और चतावनी दी कि सरकार ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ सख्त और निर्णयक कार्रवाई करेगी। उन्होंने जनता से अवैध व्यापार और संगठित अपराध से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करके कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की।

उपायुक्त रियासी ने राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की अतिक्रमण हटाने, सख्त प्रवर्तन उपाय करने का आह्वान

रियासी

उपायुक्त निधि मालिक ने जमाबंदी, राज भूमि से अतिक्रमण हटाने, राजस्व अदालत के मामलों की स्थिति, समित्वा योजनाओं, जन सुगम पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं एवं भूमि अधिग्रहण मामलों सहित भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग की एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राजस्व प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

तहसीलदारों को एक सप्ताह के भीतर डिजिटल जमाबंदियों का सत्यापन पूरा करने और दोहरे सत्यापन से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कहा गया।



राज्य की भूमि की सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने राजस्व अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई नया अतिक्रमण न हो और

करने के लिए विशेष रूप से स्कूलों में क्षेत्रीय दौरे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उपायुक्त ने निर्माण नियमों का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया, अधिकारियों से नागरिकों को उचित अनुमति प्राप्त करने और अवैध संरचनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।

उन्होंने पारदर्शी और प्रभावी राजस्व प्रबंधन के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता देहराई, ऑनलाइन सेवाओं को सुव्यवसित करने और समग्र सेवा वितरण में सुधार के लिए सक्रिय उपायों का आह्वान किया। बैठक में एसीआर अंशुमाली शर्मा, एसडीएम पीयूष धोत्रा, एसडीएम मजाहिर हुसैन और तहसीलदार उपस्थित थे।

उपराज्यपाल ने अतिरिक्त सचिव जतिन किशोर और चिकित्सक विजय सागर को विदाई दी

जम्मू

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में अतिरिक्त सचिव जतिन किशोर और चिकित्सक विजय सागर को विदाई दी। समारोह में राजभवन के अधिकारी भी उपस्थित थे। उपराज्यपाल ने जतिन किशोर और विजय सागर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके पेशेवर आचरण और ईमानदारी से समर्पण हेतु उनकी सराहना की जिसके साथ उन्होंने राजभवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उपराज्यपाल ने जतिन किशोर को गांदरबल का उपायुक्त नियुक्त किया। डॉ. विजय सागर 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने उनके अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और भविष्य में सफलता की कामना की।

उपायुक्त पुंछ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा, सामुदायिक कल्याण उपायों की समीक्षा की 4 पात्र लाभार्थियों के पक्ष में पीएमएमएसवाई लाभों को मंजूरी दी गई



पुंछ

उपायुक्त पुंछ विकास कुड़ल ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सीमा सुरक्षा और नियंत्रण रेखा के पास सामुदायिक कल्याण में सुधार पर

उपायुक्त ने महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं को सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अंतर-एजेंसी सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य सामाजिक मुद्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने विष्वसनीय पानी और बिजली आपूर्ति का भी आह्वान

किया और विभागों को सीमावर्ती क्षेत्रों में पशु चिकित्सा, चिकित्सा शिविर और नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसके अलावा, उपायुक्त ने सीमा सड़क संगठन को पुंछ शहर के लिए एक नए वैकल्पिक पुल की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कहा। बैठक में एडीसी, अतिरिक्त एसपी, एसीआर, सीपीओ, एसीडी, सीएमओ, तहसीलदार और भारतीय सेना, बीएसएफ, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच, उपायुक्त ने प्रधानमंत्री मत्त्य सम्पदा योजना पर जिला स्तरीय समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की जो स्थानीय मछुआरों को आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख योजना है।

आरंभ में मत्त्य विकास अधिकारी ने पीएमएमएसवाई के तहत पंजीकृत मामलों का विस्तृत विवरण विचारार्थ प्रस्तुत किया।

गहन चर्चा के बाद, उपायुक्त ने पात्र लाभार्थियों के चार आवेदनों को मंजूरी दी, जो स्थानीय मत्त्य पालन विकास और स्थिरता प्रयासों की दिशा में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है।

बैठक में पीओ आईसीडीएस, एसीडी, सीपीओ, एचओडी जूलॉजी जीडीसी पुंछ, मत्त्य विकास अधिकारी, एडी मत्त्य पालन के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।



गांदरबल

गांदरबल के उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में आयोजित एक औपचारिक हैंडओवर समारोह में, जितन किशोर ने श्यामबीर के स्थान पर गांदरबल के उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला।

जितन किशोर, जो पहले उपराज्यपाल सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे और सचना निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, ने जिला प्रशासन के कई विषयों की उपस्थिति में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त गांदरबल गुलजार अहमद, जीएम डीआईसी बिलाल मुख्तार और मुख्य योजना अधिकारी शाहनवाज अहमद खान उपस्थित थे। उपस्थित अधिकारियों द्वारा उपायुक्त का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

2025 : सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

जेके ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है- जावेद डार परिचालन दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 537 पीएसीएस को कम्प्यूटरीकृत किया गया

जम्मू

संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 'सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है' थीम के तहत 2025 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, सहकारिता, कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा। जम्मू-कश्मीर ने किसानों और ग्रामीण समुदायों के कल्याण और प्रगति के लिए सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रतीक्षा की है।

उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर सहकारी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जम्मू-कश्मीर भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने पर उत्सुकता से ध्यान केंद्रित कर रहा है और यूएनओ द्वारा तय की गई थीम के तहत सभी गंभीर प्रयास किए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि 1746.27 लाख रुपये की लागत से 537 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा, जिससे जम्मू-कश्मीर में सहकारी क्षेत्र को काफी मजबूती मिलेगी। पैक्स के



डिजिटलीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि इससे परिचालन दक्षता बढ़ी है, पारदर्शिता में सुधार हुआ है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित हुआ है।

केंद्रीय मंत्रालय के तहत, पूरे क्षेत्र में सहकारी संस्थानों के आधुनिकीकरण और

लिए स्वास्थ्य देखभाल लागत कम हो गई है।

मंत्री ने कहा कि 144 प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के लॉन्च के साथ सहकारी नेटवर्क को और मजबूत किया गया है, जो वन-स्टॉप कृषि सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

मंत्री ने कहा, ये केंद्र कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देने और आवश्यक संसाधनों और ज्ञान के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और विशेषज्ञ सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं।

डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़े कदम में, ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटते हुए, पैक्स के माध्यम से 480 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। मंत्री ने कहा, ये केंद्र ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, बैंकिंग और वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण आबादी को निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित होता है।

इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए बाजार

पहुंच और सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए 61 पैक्स को किसान उत्पादक संगठनों में बदल दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि भंडारण क्षमता बढ़ाने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अलावा राष्ट्रीय सहकारी टेलाबेस पोर्टल पर सहकारी समिति के रिकॉर्ड के व्यापक अद्यतनीकरण, अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए गोदाम निर्माण के लिए छह पैक्स की पहचान की गई है। उन्होंने कह कि आधुनिकीकरण के साथ-साथ निष्क्रिय सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए भी सफल प्रयास किये जा रहे हैं। लगभग छह सहकारी सुपर बाजारों को उत्तर किया गया है और सात और के निर्माण की योजना है। इसके अलावा, ब्लॉक मुख्यालयों पर तेरह सहकारी मिनी-सुपर बाजार भी विकसित किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि पांच सहकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं और विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है।

मुख्य सचिव ने एफसीएसएंडसीए और मेट्रोलॉजी विभागों के कामकाज की समीक्षा की हर परिस्थिति में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश

जम्मू

मुख्य सचिव अटल डुहू ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग और कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग के कामकाज की समीक्षा हेतु नागरिक सचिवालय, जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक की अद्यक्षता की।

बैठक में आयुक्त सचिव एफसीएस एड सीए जुबैर अहमद, नियंत्रक लीगल मेट्रोलॉजी विभाग जे-एंड-के अनुराधा गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने दोनों विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए अवैध वितरण इकाइयों के संचालन को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण उपायों की ओर मजबूत करने के लिए एक व्यापक डेटाबेस के निर्माण और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का भी निर्देश दिया।

उन्होंने इस अवसर पर उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने वाले सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने पर जोर दिया। उन्होंने हर हाल में उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें उचित दारों पर गुणवत्ता पूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं



उपलब्ध कराई जा सकें।

अटल डुहू ने अपनी सेवाओं को जनता के लिए अधिक सुलभ और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। उन्होंने एफसीएस एवं सीए विभाग को दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली जनता को समय पर खाद्यावधि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सर्दियों के महीनों के दौरान राशन वितरण और उपलब्धता पर ध्यान दारों पर गुणवत्ता पूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं

दिया कि इन गांवों में प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उसकी पात्रता के अनुसार राशन मिले।

आयुक्त सचिव, एफसीएस एड सीए, जुबैर अहमद ने मुख्य सचिव को विभाग की प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराया, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान कवरेज, चल रहे सुधार और सिस्टम की विष्वसनीयता बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण

फोकस क्षेत्रों जैसे आवश्यक वस्तुओं की शीतकालीन स्टॉकिंग, खरीफ विपणन सीजन के दौरान धान की खरीद और अन्य भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों पर अपडेट प्रदान किया।

नियंत्रक, लीगल मेट्रोलॉजी विभाग, जम्मू-कश्मीर, अनुराधा गुप्ता ने बैठक को विभाग के उद्देश्यों और संचालन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग की सभी सेवाएँ अब जम्मू-कश्मीर सिंगल विंडो

सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं और जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत कवर की गई है। विशेष रूप से, विभाग ने अपने पोर्टल पर शुल्क मूल्यांकन के लिए एक ऑटो-गणना सुविधा शुरू की है। लाइसेंस के लिए ऑटो-नवीनीकरण सुविधा के साथ, सिस्टम को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है।

उपभोक्ता जनप्रवासों पर प्रकाश डालते हुए, नियंत्रक ने कहा कि विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों में 269 सेवा शिविर आयोजित किए हैं। 11 दिनों के औसत प्रसंसकरण समय के साथ, एलएमडी प्राप्त और निपटाएं गए ऑनलाइन आवेदनों की संख्या में तीसरे स्थान पर है। सेवा वितरण के अलावा, विभाग शिविरों और सोशल मीडिया पहलों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए विभाग नियमित रूप से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाता है। हाल ही में, इसने कश्मीर घाटी में गैर-मानक हेलमेट और अनधिकृत पेट्रोल पंपों के खिलाफ अभियान चलाया।

जिला मजिस्ट्रेट जम्मू ने जिले भर में बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन ऑडिट का निर्देश दिया

जम्मू

जिला मजिस्ट्रेट जम्मू सचिव कुमार वैश्य ने जिले में सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं से उनकी वर्तमान अपशिष्ट निपटान प्रथाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रोटोकॉल के अनुपालन में कमी भी शामिल है। जिले भर में बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लक्ष्य के साथ बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरबख्त सिंह को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, निपटान और प्रसंस्करण सुविधाओं की परिचालन स्थिति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। पूरी कवायद अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त शेर सिंह की देखरेख में होनी है।

इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट ने सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान नियमों के सम्बन्धित अनुपालन की अनिवार्यता के बारे में पूरी तरह से सूचित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। सुविधाओं को उचित सॉफ्टवेयर समाधानों का उपयोग करते हुए अपशिष्ट प्रसंस्करण और स्थानांतरण के लिए मजबूत ट्रैकिंग और स्ट्रिक्विंग तंत्र लागू करने का भी निर्देश दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपशिष्ट निपटान निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो, जिससे हमारे जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता की रक्षा हो सके।

बैठक में कायरकारी अभियंता पीएचई राजेश शर्मा, मंडल अधिकारी एसपीसीबी, स्वास्थ्य अधिकारी जेएमसी डॉ. विनोद शर्मा, एचओडी मेडिसिन गवर्नर्मेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉ. विजय कुंडल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. समीना नजीर, नोडल अधिकारी बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन डॉ. ज्योति भाऊ और अन्य संबंधित अधिकारियों की भागीदारी देखी गई।

उपायुक्त ने जिला पशु अस्पताल सांबा में पशु चिकित्सक देखभाल सुविधाओं का जायजा लिया



सांबा

पशु कल्याण और सार्वजनिक सेवा वितरण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता के प्रदर्शन में, उपायुक्त सांबा राजेश शर्मा ने पशुधन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल उपायों को सुविधाओं के बदले दिया है। आज जिला पशु अस्पताल का अध्यक्षित निरीक्षण किया गया।

दौरे में परिचालन दक्षता, कर्मचारियों के प्रदर्शन और बुनियादी ढांचे की स्थिति का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिले में कृषक समुदाय

को सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए कई निर्देश देखी गईं।

उपायुक्त ने अस्पताल संचालन और कर्मचारियों के प्रदर्शन, रक्त परीक्षण मशीनों और नसबंदी सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के मूल्यांकन, बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन, दूरदराज के थांगों तक पहुंचने के लिए मॉबाइल पशु चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की।

उपायुक्त ने परिचालन चुनौतियों को समझने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों के साथ सीधे बातचीत की और उन्हें सुविधाओं और सेवाओं

के उत्तरान में प्रशासन के पूर्ण समर्थन का आव्वासन दिया। उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखने और जिले भर में पशुधन मालिकों को सक्रिय सेवा वितरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

यह निरीक्षण सांबा जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रशासन की व्यापक पहल को दर्शाता है, जिसमें पशु चिकित्सा सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो सीधे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और ज्यादा आजावीका को प्रभावित करता है।

उपराज्यपाल ने एम्स जम्मू में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया



विशेषज्ञों से एसओपी को अद्यतन रखने और जीवन-धातक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति यों की जरूरतों, परिवारों की भलाई, दर्द और पीड़ा को कम करने और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने के प्रति अधिक संवेदनशील होने का आग्रह किया।

निजी क्षेत्र को प्रशासन के साथ मिलकर पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में प्रशासक देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए कहा।

सभी विशेषज्ञों और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर को बहु-क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि प्रशिक्षित देखभाल करने वालों का एक मानव संसाधन पूल उपलब्ध कराया जा सके।

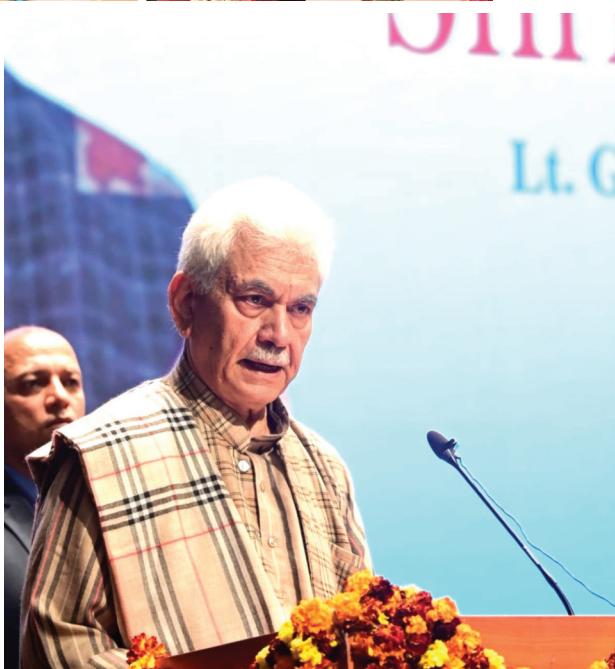
लाइलाज बीमारी से पीड़ित रोगियों के जीवन की गुणवत्ता के लिए उपशासक देखभाल में प्रगति और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 800 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि विचार-विमर्श में शामिल होंगे।

उपराज्यपाल ने एम्स जम्मू में रेडियोथेरेपी ऑन्कोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, एम्स पेन पॉलिसी लॉन्च की।

सांबा

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एम्स जम्मू में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

लाइलाज बीमारी से पीड़ित रोगियों के जीवन की गुणवत्ता के लिए उपशासक देखभाल में प्रगति और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 800 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि विचार-विमर्श में शामिल होंगे। तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आईएपीसी जैएंडके



चेटर और एम्स, जम्मू द्वारा किया जा रहा है। अपने मुख्य भाषण में, उपराज्यपाल ने विशेषज्ञों से मानक संचालन प्रक्रियाओं को अद्यतन रखने और जीवन-धातक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जरूरतों, परिवारों की भलाई, दर्द और पीड़ा को कम करने और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने के प्रति अधिक संवेदनशील होने का आह्वान किया।

उपराज्यपाल ने निजी क्षेत्र से पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में प्रशासक देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए प्रशासन के साथ काम करने को कहा।

उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में, प्रशासन ने 2022 में सभी जिलों में 10 बिस्तरों वाले अत्यधिक प्रशासक और वृद्धावस्था देखभाल वार्ड स्थापित किए थे। हमने कुछ हद तक शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाठने का प्रयास किया है। हमारा उद्देश्य लोगों के दरवाजे पर चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता पहुंचाना है।

उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि सभी विशेषज्ञों और भारतीय प्रशासक देखभाल संघ को बहु-क्षेत्रीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि प्रशिक्षित देखभाल करने वालों का एक मानव संसाधन पूल उपलब्ध कराया जा सके।

उपराज्यपाल ने कहा, उपशासक देखभाल में स्वास्थ्य परिस्थिति की

देखभाल पेशेवरों की रोगियों के दर्द और पीड़ा को कम करने की नीति जिम्मेदारी है। दर्द प्रबंधन के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाने के अलावा, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को ऐसे रोगियों की देखभाल में निरंतरता के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र में उपचारात्मक देखभाल और प्रशासक देखभाल के निबंध एकीकरण के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर सामुदायिक जागरूकता, उपशासक सहायता और दर्द प्रबंधन के लिए एक समान एसओपी तैयार की जा सकती है।

उन्होंने कहा, प्रशासक देखभाल प्रणाली लगातार विकसित हो रही है और हमें रणनीतिक ढांचे, एसओपी और इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर काम करने की जरूरत है।

उपराज्यपाल ने कहा, आबादी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और विशेष सेवाओं में अंतर को पाठने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

उपराज्यपाल ने कहा, 2050 तक, भारत की कुल जनसंख्या का 20.8 प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा। बुजुर्ग आबादी में इस वृद्धि के लिए हमें एक मजबूत देखभाल अर्थव्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे बुजुर्ग स्वस्थ, सम्मानजनक और पूर्ण जीवन जी सकें।

उपराज्यपाल ने कहा, उपशासक देखभाल में स्वास्थ्य परिस्थिति की



उन्होंने एक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज विकसित करने का भी सुझाव दिया जिसमें नियमित जांच, वृद्धावस्था देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और उपशासक देखभाल शामिल है।

इस अवसर पर उपराज्यपाल ने एम्स जम्मू में रेडियोथेरेपी ऑन्कोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उन्होंने एम्स दर्द नीति लॉन्च की और दर्द मुक्त रोगी देखभाल के एम्स जम्मू के दृष्टिकोण की सराहना और दर्द प्रबंधन के लिए एक समान एसओपी की जांच की।

उन्होंने प्रशासक देखभाल के सिद्धांतों के आधार पर विशेष देखभाल के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर की भी सराहना की।

इस बीच, उपराज्यपाल ने एम्स, जम्मू में विभिन्न ब्लॉकों का निरीक्षण किया और चिकित्सा कर्मचारियों के साथ बातचीत की। एनेसेसियोलॉजी विभाग की मानक संचालन प्रक्रियाएं और कीमोथेरेपी की रोगी सूचना पुस्तिका भी लॉन्च की गई।

एम्स जम्मू में रेडियोथेरेपी ऑन्कोलॉजी सुविधा की स्थापना से रोगियों को विकिरण चिकित्सा के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे क्षेत्र के भीतर समय पर निदान और उपचार सुनिश्चित हो सकेगा।

यह सेवा कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी, उन्नत रेडियोथेरेपी तकनीकों, व्यक्तिगत उपचार योजनाओं और बहु-विषयक देखभाल की पेशकश करेगी। आईसीएमआर के ग्रामीय कैंसर डेटा प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल-आधारित कैंसर रेजिस्ट्री भी शुरू की गई है जो प्रभावी कैंसर देखभाल संचालन और रणनीतियों को आकार देने में सहायता करेगी।

एम्स जम्मू में 08 उन्नत ऑपरेशन थिएटरों वाले ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में वास्तविक समय के चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया। उन्होंने एम्स जम्मू के दृष्टिकोण की सराहना और दर्द प्रबंधन के लिए एक समान एसओपी की जांच की।

उन्होंने प्रशासक देखभाल के सिद्धांतों के आधार पर विशेष देखभाल के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर की जांच की।

उन्होंने कहा, एम्स जम्मू के दृष्टिकोण की सराहना और दर्द प्रबंधन के लिए एक हाइब्रिड ऑटो शामिल है। ऑटो सुविधा में स्टीक और बेहतर सीखने के लिए हाई-डिजिटल ऑडियो-विजुअल सिस्टम, सर्जिकल प्रक्रियाओं में दक्षता सुनिश्चित करने वाला मॉड्यूलर डिजाइन है।

कार्यकारी निदेशक और सीईओ एम्स जम्मू डॉ. शक्ति कुमार गुप्ता, अध्यक्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर प्रोफेसर सुषमा भट्टाचार्य, अध्यक्ष आईएपीसी जम्मू-कश्मीर चैटर डॉ. रोहित लाहौरी, आयोजन सचिव डॉ. सुनान गुप्ता, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ, आईएपीसी के सदस्य और चिकित्सा समुदाय उपस्थित थे।